ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS THEREON

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF TOURISM

RAJYA SABHA

STARRED QUESTION NO.151

ANSWERED ON 03.08.2023

CONSTRUCTION OF CRUISE BERTH IN OUTER HARBOR

151 SHRI V.VIJAYASAI REDDY:

Will the Minister of **TOURISM** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that construction of Cruise Berth in Outer Harbor of Visakhapatnam Port was sanctioned five years ago with an estimated expenditure of nearly ₹ 40 crore ;

(b) whether it is also a fact that the project is yet to be completed and not even 50 per cent of amount has been utilized by Government;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) by when the above project is going to be completed?

ANSWER

THE MINISTER OF TOURISM (SHRI G. KISHAN REDDY)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

****

STATEMENT IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.151 ANSWERED ON 03.08.2023 REGARDING CONSTRUCTION OF CRUISE BERTH IN OUTER HARBOR**.**

(a) to (d): On request from the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, a proposal for part funding of Development of Cruise-Cum Cargo Terminal at channel berth in outer harbour of Visakhapatnam Port by the Vishakhapatnam Port Trust (VPT) was approved by the Ministry of Tourism (MoT) in 2018-19.

The total approved project cost as given by Vishakhapatnam Port Trust (VPT) was Rs.77 crore of which 50 percent funding (i.e. Rs.38.50 crore) was to be done by the Ministry of Tourism and the remaining expenditure was to be met by Vishakhapatnam Port Trust (VPT) from their internal resources. Out of the approved MoT funding of Rs.38.50 crore, Rs.29.91 crore (which is 77.6 percent of the approved funding) has already been released. This has been fully utilised by Vishakhapatnam Port Trust (VPT).

For part funding of the project of Vishakhapatnam Port Trust (VPT), Ministry of Tourism Sanctioned financial assistance in December 2018. Subsequently, VPT applied for Environment clearance. State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) approved the Terms of Reference (ToR) with condition to obtain No Objection Certificate (NOC) from Indian Navy in June, 2019. The No-objection Certificate from Indian NAVY was received in July 2021. Environmental Clearance for the project was issued by SEIAA in October 2021.

In the meantime, Covid-19 (1st wave) Lock down was also imposed by Government from March 2020 and again partial restrictions was imposed due to Covid-19 (2nd wave) upto April, 2021

Tender (both berth and terminal building) on Engineering Procurement and Construction_mode was processed in September, 2021. But only single unqualified bidder participated. Hence, it was cancelled as per the norms and the work was split in two packages i.e., (1) Construction of Cruise Berth and (2) Construction of Cruise Terminal Building. Finally, the work commenced from 2nd week of February, 2022.

The project has been closely monitored in the Ministry of Tourism and major works like berth construction, cruise building, structural work etc have been completed. The project is ready for inauguration after completion of all major components.

******

भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 151

गुरूवार, 3 अगस्त, 2023/12 श्रावण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

बाहरी हार्बर पर क्रूज़ बर्थ का निर्माण

151 श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विशाखापटनम बंदरगाह के बाहरी हार्बर में लगभग रु 40 करोड़ के अनुमानित व्यय से क्रूज़ बर्थ के निर्माण को पांच साल पहले स्वीकृति दी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है और सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राशि का भी उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त परियोजना कब तक पूर्ण हो जायेगी?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

बाहरी हार्बर पर क्रूज़ बर्थ का निर्माण के संबंध में दिनांक 03.08.2023 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 151 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुरोध पर विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) द्वारा विशाखापटनम पत्तन के बाहरी बंदरगाह में चैनल बर्थ पर क्रूज-कम-कार्गो टर्मिनल के विकास के आंशिक वित्तपोषण के एक प्रस्ताव को वर्ष 2018-19 में अनुमोदित किया था ।

विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के अनुसार अनुमोदित परियोजना लागत कुल 77 करोड़ रु. थी जिसमें से 50 प्रतिशत वित्तपोषण (अर्थात 38.50 करोड़ रु.) पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाना था और शेष व्यय विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना था । पर्यटन मंत्रालय द्वारा 38.50 करोड़ रु. के अनुमोदित वित्तपोषण में से 29.91 करोड़ रु. (जो अनुमोदित वित्तपोषण का 77.6 प्रतिशत है) पहले ही जारी कर दिए गए हैं । विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) द्वारा इस राशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है ।

विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) की परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए पर्यटन मंत्रालय ने दिसम्बर 2018 में वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी थी । इसके बाद वीपीटी ने पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए आवेदन किया था । राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) ने जून 2019 में भारतीय नौसेना से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त किए जाने की शर्त पर विचारार्थ विषय (टीओआर) को अनुमोदित किया । भारतीय नौसेना से जुलाई 2021 में अनापत्ति प्रमाणपत्र मिल गया था । एसईआईएए द्वारा इस परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति अक्तूबर 2021 में जारी की गई ।

इस बीच सरकार द्वारा मार्च 2020 से कोविड-19 (पहला दौर) लॉकडाउन भी लगा दिया गया था और फिर अप्रैल 2021 तक कोविड-19 (दूसरा दौर) के कारण आंशिक प्रतिबंध लगाए गए थे ।

इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड संबंधी निविदा (बर्थ और टर्मिनल बिल्डिंग दोनों के लिए) की कार्रवाई सितंबर 2021 में शुरू की गई लेकिन केवल एक अयोग्य बोलीकर्ता ने भाग लिया । अतः नियमानुसार इसे रद्द कर दिया गया था और कार्य को दो पैकेजों अर्थात (1) क्रूज बर्थ का निर्माण और (2) क्रूज टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण में विभाजित कर दिया गया । अंततः फरवरी 2022 के दूसरे सप्ताह से काम शुरू हुआ ।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस परियोजना की पूरी निगरानी की गई है और बर्थ निर्माण, क्रूज बिल्डिंग, ढांचागत निर्माण कार्य आदि जैसे प्रमुख निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं । सभी प्रमुख घटक पूरे होने के बाद यह परियोजना उद्घाटन के लिए तैयार है ।

*****

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, the former Chairman of Visakhapatnam Port Trust is on record saying that the cruise terminal building and cruise berth would be operational by April, 2023. We are in the month of August and so far, the operations have not been started, the terminal building is not ready and it is not ready for inauguration. In the last para of the reply given by the hon. Minister, it has been stated that it would be ready for inauguration after completion of all major components. Those major components are...

MR. CHAIRMAN: Please come to the question.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Yes, Sir. The major components are cruise berth construction, cruise terminal building and structural works, which are yet to be completed. What is the Minister's stand on this?

श्री अजय भट्ट : मान्यवर, बीच में कोरोना की वजह से इसमें थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है। 2021 और 2022 में कोरोना की वजह से विलंब के कारण थोड़ी परेशानी सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में हुई है। कोविड-19 का पहला दौर 2020 के मार्च में और दूसरा दौर 2021 में रहा, जिसके कारण इस पर प्रतिबंध लग गया। हमने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज़ के अनुरोध पर ही यह पैसा दिया था। हमने कहा कि हम इसका वित्त पोषण करेंगे और जितना भी पैसा लगेगा, हम देंगे।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*।)

हमने तो वीपीटी को 77 करोड़ रुपए, उसने जो पूरी लागत बताई थी कि इतने पैसे में यह पूरा पोर्ट बनेगा, उसका आधा, यानी 38.50 करोड़ रुपए समय पर दे दिए थे। अगर देखा जाए, तो जो पूरी अनुमोदित धनराशि है, उसके अनुसार ..

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: He is reading from the reply. ...*(Interruptions)*.. .

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप ब्रीफली रिप्लाई दें। प्लीज़, आप संक्षेप में, ब्रीफली रिप्लाई दें।

श्री अजय भट्ट : सर, यह बिल्कुल बन कर तैयार है। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसके संबंध में मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे जिस समय चाहेंगे, उस समय हम उसका उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह काम वीपीटी को करना है। हम तो इसमें सहायक हैं, हम पैसा देते हैं। उसने कहा कि आप हमें आधा पैसा दे दीजिए, तो हमने पैसा दे दिया है। अभी बैठक में भी उन्होंने कहा कि वे इसकी तैयारी कर रहे हैं। आज सारी चीजें बन कर तैयार हो चुकी हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary, Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, my permission is not required for the Minister to inaugurate it. It is unreasonable and unwarranted. Now, I come to my second supplementary. Will the Minister consider increasing the passenger capacity from present 2,500 to 5,000, and also provide helicopter services and sea-plane services, like, they have provided in Cochin Cruise Terminal? Let him be very clear in his reply.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That he has to give.

श्री अजय भट्ट : मान्यवर, हम इसमें एक किस्म से अपनी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज़ के साथ ही हैं। वह जो भी माँग रही है, हम दे रहे हैं। हमारे जितने पोर्ट्स प्रारंभ हो रहे हैं, हम उनमें भी सहायता कर रहे हैं। हम उनको सहायता देते जा रहे हैं। निकट भविष्य में इसका उद्घाटन भी होगा। जहाँ-जहाँ सी-प्लेन का सर्वे चल रहा है, अगर वह इसमें आएगा, तो भविष्य में देखा जाएगा। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि हम इसमें क्या-क्या करेंगे, किस टाइप से यह होगा, तो अभी हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटक हैं, उन्होंने आना प्रारंभ कर दिया है। महोदय, हम इसको ही नहीं, बहुत सारे अन्य पोर्ट्स को भी सहायता कर रहे हैं और जब कोई डिमांड आती है, तो पैसा भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी ने 13 जनवरी को गंगा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए, डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी तक, विश्व के सर्वाधिक लम्बे रिवर क्रूज़ को हरी झंडी दिखाई। यह जलमार्ग सफलता से लगभग 32 किलोमीटर के जलमार्ग को कवर करते हुए, बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंच गया है। अगर कहीं भी इस तरह के कार्य को करना होता है, तो पर्यटन विभाग सहायता करने के लिए हर समय तत्पर रहता है।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: When is it going to be inaugurated?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, Vijayasai Reddy ji. Now, Shri G.K. Vasan.

SHRI G.K. VASAN: Sir, Tamil Nadu has three major ports. Chennai port has a well-facilitated cruise terminal, catering to the needs of lakhs and lakhs of passenger ships and cruise ships. Chennai-Mahabalipuram-Puducherry is a favourite destination for cruise tours which will earn valuable revenue for the Central Government. I would like to know from the hon.Minister if the Ministry has any idea of promoting cruise tourism in Tamil Nadu, especially on this favourite sector.

श्री अजय भट्ट : बिल्कुल, मान्यवर। ऐसे कई सारे स्थान हैं, जहां पर हम लोग अपने सहायक विभाग को सहायता कर रहे हैं। तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के लिए हमने 17.24 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने जिस तरह की डिमांड की है, उनको वह धनराशि हम दे रहे हैं। इसी तरह अन्य जगहों पर भी यह कार्य हो रहा है।

संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले यह बात कही थी। हमारा लगातार यह प्रयास रहता है कि जैसे-जैसे कंसर्न्ड स्टेट या कंसर्न्ड डिपार्टमेंट इसमें काम करेंगे, वे हमसे जितनी भी भागीदारी चाहेंगे, वह भागीदारी देने के लिए हम तत्पर रहेंगे।

SHRI G.K. VASAN: Sir, I would only request the Minister to consider it.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, first of all, I would congratulate the hon. Prime Minister, the Minister of Tourism and the Minister of Ports for a world-class cruise terminal in Vishakhapatnam. The question is about this. It is the only state-of-the-art cruise terminal. It is almost ready. I visited this personally on July 17. It is almost ready for inauguration. My question to the hon. Minister is this. It is an infrastructure of pride for Vishakhapatnam. Cruise operations are going to start very soon. International cruise liners have shown interest in operating from Vishakhapatnam.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your question, please.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: My question is: Will the Ministry take appropriate steps to talk to the concerned Ministry, the Ministry of Home Affairs, to commence customs operations so that we can have international cruise operations?

श्री अजय भट्ट: बिल्कुल मान्यवर। इस पर पूरी वार्ताएं चल रही हैं। शीघ्र ही इसका उद्घाटन भी होगा और संचालन भी प्रारम्भ हो जाएगा।

श्री गुलाम अली: डिप्टी चेयरमैन सर, मैं एप्रिशिएट करता हूं कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी की क़ियादत में, जम्मू-कश्मीर में टूरिज़्म का इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर से यह क्वेश्चन है कि जम्मू-कश्मीर में ऑल-टेरेन व्हीकल की जगह पहले घोड़ों का इस्तेमाल होता था, जैसे गुलमर्ग का एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा। जब घोड़ों की जगह ऑल-टेरेन व्हीकल इस्तेमाल होंगे, तो हज़ारों की तादाद में जो घोड़े वाले हैं, वे बेरोज़गार हो जाएंगे।

ऑनरेबल मिनिस्टर से मेरा यह सवाल है कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है, जिससे घोड़े वालों का रोज़गार भी बना रहे? क्या आपका ऐसा कोई मैकेनिज़्म तैयार करने का कोई प्लान है?

श्री अजय भट्ट : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्रता से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। इस पर स्टेट जैसा डिसाइड करती है, वैसा करे, हम लोग तो

यहां से गाइडलाइन देते हैं। अगर स्टेट हमें कोई प्रोजेक्ट देता है और अगर वह प्रोजेक्ट हमारे पैरामीटर पर ठीक उतरता है, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। स्टेट जो नियम बनाता है, अगर वे ठीक हैं, तो स्टेट ही उनको चलाएगा, क्योंकि यह स्टेट का ही सब्जेक्ट है।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 152.